

भागरा में ऐतिहासिक स्थलों पर टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग

1083 श्री रामजीलाल सुमन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आपातस्थिति के दौरान भागरा के ऐतिहासिक स्थलों पर यात्रियों से 2 रुपये प्रति टिकट की दर से टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि को किम प्रयोजन के लिये खर्च किया गया, और

(ख) राज्य सरकार से मत्तणा करके इसको घटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र ख-३) (क) और (ख) यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भागरा में केन्द्र द्वारा सरक्षित चार स्मारकों पर प्रति दर्शक से पचास पैसे प्रवेश शुल्क वसूल करता है। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि सरकार को राजस्व के रूप में दी जाती है। स्मारकों के रख-रखाव के लिये बजट में अलग से व्यवस्था है।

इन चार स्मारकों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति दर्शक स.रु. 1 50 की अतिरिक्त राशि एकत्र की जा रही है। भारत सरकार ने इस व्यवस्था को अनुमोदित नहीं किया है और इस मामले का राज्य सरकार के साथ उठाया है। राज्य सरकार ने जो पक्ष लिया है, वह यह है कि उसके द्वारा सगृहीत-इस अतिरिक्त शुल्क की आय का प्रयोग भागरा में सामान्य रूप से यात्रियों की सुविधाओं को सुधारने और उनके रख-रखाव के लिए विशेषरूप से इन स्मारकों के लिये होगा।

बिहार को पशु पालने के लिए केंद्रीय अनुदान

1085 श्री बालेधर प्रसाद यादव क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकार का विचार पशुपालन के लिये ऋण देने तथा बिहार के कमजोर वर्गों को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) तथा (ख) कमजोर वर्गों के लाभ के लिए बिहार महित सभी राज्यों और सब राज्य क्षेत्रों में विशेष पशुपालन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सकर प्रजनित बछड़ों को पालने, प्रत्येक 50 से 100 पक्षिया के कुक्कुट पालन यूनियो, 3 गुरको के सुधर यूनियो तथा 20 भेड़ों व एक दुग्ध के भेड़ यूनियो की व्यवस्था करने का उद्देश्य है।

कुक्कुट पालन, सुधर पालन तथा भेड़ यूनियो के मामले में अभिज्ञात लघु कृषकों को उत्पादन यूनियो को स्थापित करने के लिये अपेक्षित पूँजी निवेश के 25 प्रतिशत के हिस्से से जबकि सीमांत कृषकों व कृषि श्रमिकों को 33% प्रतिशत के हिस्से से राज्य सहायता दी जाती है। शेष पूँजी निवेश की व्यवस्था लाभान्धोगियों को ऋण के रूप में सहायता से करनी होती है। 4 से 28 मास के सकर प्रजनित बछड़ों को दाना-चारा देने के लिए लघु तथा सीमांत कृषकों की श्रेणी के अभिज्ञात लाभान्धोगियों को दाने-चारे की कुल लागत के 50 प्रतिशत के हिस्से से तथा कृषि श्रमिकों को 66% के हिस्से से राजसहायता दी जाती है।